EDITORIAL

Message of the May Day

At Present scenario May Day is more relevant as the achieved facilities to workers after a big sacrifices of Martyrs of Chicago and at other places are in danger due to pro corporate developed policy of the governments.

May Day remind us the huge scarifice of workers and their unions to assert that the workers be treated as human being and not as animals. Rather one could claim that the discourse of human rights was initiated by the labour movement in the human history. They are cry for fixed working hours 8 hours for work, 8 hours for rest and 8 hours for recreation and rejuvenation with the family echoed in various parts of the world in19th century. In the India to the demand of fixed hours of work behin from 1866 when the unions were yet to be born sector wise, as till then the collectives for common cause was through community bases. It was in 1886 that the workers in Chicago began their protest strike on 1st May, that followed the bomb explosion by the conspirator to find an excuse to crush the moment. The eight leaders arrested, four of them where given death sentence, two died in jail and two were given life imprisonment.

It was in 1889 that in an international meeting of workers associations where Karl Marx talked of cry of working class, the incidents of May protest in Chicago and suggested to observe May Day for paying tributes to the Martyrs of that struggle and to continue the struggle for fix working hours. It was from 1890 that the day begin to be observed with a slogan "Workers of the world Unite".

The working class of the world over is facing severe situation of reversal of various labour rights won over after hard and prolonged battle including the rights to fixed working hours and right to strike. The attack on labour rights and unions is the tool for the pro-corporate government to weaken and stifle the collective bergaining to continue their support to the monopoly Capitalist for super profits overriding the rights of working masses.

May Day 2023 have been observed with more vigor by workings class this year of several pressing reasons. Taking into cognizance of the political developments which are moving at very fast pace on every front in the year before General Election in 2024,it is utmost important to assess the situation.

In India also we were observing May Day from 1923.

The economy is further in deterioration with the ever-rising prices of essential commodities, the cerals, pulses, wheat flour, rice, cooking oil, cooking gas (at above Rs. 1200 per cylinder), retail milk prices rise more than 15% in last one year. the cost of education and health care rising where as the income/ways increase is not taking place, it is becoming very difficult and substances of the poor working masses with every passing day.

Budget did not address long term employment and creation of quality jobs 10 million new job seeks enter the job merket every year Unemployment is at its peak of 34% Budget talks about demand based skilling. Skilling comes with formal education. Leaving behind the reality of formal edcation in india, skilling makes no sense. New age courses for industry 4.0 aims at a very small section of technically educated youth leaving behind the large section of the deserving. The budget mentioned for spending on higher education, in actual it is a blueprint mentioned for spending on higher education, in actual it is a blueprint all ready to bring foreign universities. BJP government has only been allocating less than 3% of GDP on education so far. Reduced public

spending on health has made poverty doles to farmers which is the election gimmick. The relief of women and senior citizens by way of enhancing the limit of deposit does not translate into any big benefit. Wedening Gender employment wase disparity and dwindling women enpowerment rate was not addressed.

The Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) were not adequately addressed. what's given by way of enhancing guarantee is too a small for the huge sector, that is the engine of growth and employment generator.

No attempt to increase tax income by taxing and rich and corporates. The borrowings to make up deficit is already visible. India's debt burden is already heavy and further burden increases and debt servicing load.

Budget note only failed for common man. It was passed without discussion in the Parliament. It has happened for the first time in the history. Even the prebudget consulations were converted into mockery, and the Central Trade unions had boycotted it.

Last the circumstances stated above the May Day message is more relevant and it should be taken a serious care by the working class.

The united struggle is only weapon for the workers to protect their interest and to save the achievement of our martyrs.

Mazdoor Ekta Zindabad

NFTE- Zindabad

संपादकीय

मई दिवस का संपादकीय संदेश

वर्तमान परिचय में मई दिवस अधिक प्रासंगिक है क्योंकि शिकागो और अन्य स्थानों के शहीदों के बड़े बलिदान के बाद श्रमिकों को प्राप्त सुविधाएं सरकारों की कॉर्पोरेट समर्थक नीति के कारण खतरे में हैं।

मई दिवस हमें याद दिलाता है कि श्रमिकों और उनकी यूनियनों के बलिदान का फल यह है कि श्रमिकों को इंसानों के रूप में माना जाता है न कि जानवरों के रूप में। बल्कि कोई यह दावा कर सकता है कि मानव अधिकारों की चर्चा मानव इतिहास में श्रमिक आंदोलन द्वारा शुरू की गई थी। वे निश्चित काम के घंटों के लिए जिसमे 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए, और 8 घंटे परिवार के साथ के लिये,19वीं शताब्दी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्षरत रहे। भारत में काम के निश्चित घंटे की मांग 1866 से शुरू हुई जब यूनियनों का जन्म अभी तक क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ था, तब तक सामान्य कारण का सामूहिक सामुदायिक आधार था।1886 में शिकागो में श्रमिकों ने पहली मई को अपनी विरोध हड़ताल शुरू की, जिसके बाद साजिशकर्ताओं द्वारा बम बिस्फोट किया गया, आठ नेताओं की गिरफ्तारी के लिये बहाना खोजा गया तथा उनको गिरफ्तार किया गया जिनमें से 4 को मृत्युदंड, 2 को आजीवन कारावास दिया गया, 2 की मृत्यु जेल में ही हो गई। यह 1889 में था कि श्रमिक संघों की एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में जहां कार्ल ने श्रमिक वर्ग के बलिदान को याद करने की शुरुआत की, शिकागो में मई के विरोध की घटना को चिन्हित किया और संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया। 1890 में यह नारा दिया गया की। दुनिया के कामगारों एक हों। दुनिया भर में मजदूर वर्ग काम के घंटे तय करने के अधिकार और हड़ताल के अधिकार सहित दिल से और लंबी लड़ाई के बाद विभिन्न श्रम अधिकारों के उलटने की एक वरिष्ठ स्थिति का सामना कर रहा है। श्रम अधिकारों और यूनियनों पर हमला सरकार हथियार के रुप में प्रयोग करती है जिससे सुपर मुनाफे के लिए एकाधिकार पूंजीपति को अपना समर्थन जारी रखा जा सके। इस वर्ष मई दिवस 2023 को मजदूर वर्ग द्वारा और अधिक व्यापक रूप में मनाया गया है, जो राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए कई कारणों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्थिति का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत में आवश्यक वस्तुओं, अनाज, दाल, गेहूं का आटा, चावल, खाना पकाने के तेल, रसोई गैस (1200 रुपये प्रति सिलेंडर से ऊपर) की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ अर्थव्यवस्था और भी खराब हो रही है, पिछले एक सालमें खुदरा दूध की कीमतों में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ रही है जहां आय में वृद्धि नहीं हो रही है, यह हर गुजरते दिन के साथ गरीब मेहनतकश जनता के लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है।

बजट ने दीर्घकालिक रोजगार और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के सृजन को संबोधित नहीं किया। हर साल बाजार में 10 मिलियन नए नौकरी चाहने वाले प्रवेश करते हैं। बेरोजगारी 34% के चरम पर है। बजट मांग आधारित कौशल की बात करता है। स्किलिंग औपचारिक शिक्षा के साथ आता है। भारत में औपचारिक शिक्षा की वास्तविकता को पीछे छोड़कर स्किलिंग का कोई अर्थ नहीं है। उद्योग 4.0 के लिए नए युग के पाठ्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी रूप से शिक्षित युवाओं के एक बहुत छोटे वर्ग को योग्य लोगों के बड़े हिस्से को पीछे छोड़ना है। उच्च शिक्षा पर खर्च करने के लिए जिस बजट का जिक्र किया गया है, वह असल में विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने का खाका है। भाजपा सरकार अब तक शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3% से कम राशि आवंटित कर रही है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च की कमी ने भारत में गरीबी को बढ़ा दिया है। किसानों को खैरात देने का दिखावा किया जाता है जो चुनावी नौटंकी

है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को जमा की सीमा बढ़ाकर राहत देने से कोई बड़ा फायदा नहीं होता है। लैंगिक रोजगार का विस्तार असमानता और घटती महिला सशक्तिकरण दर को संबोधित नहीं किया गया था।

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था। गारंटी बढ़ाने के माध्यम से जो दिया गया है वह विशाल क्षेत्र के लिए बहुत छोटा है, जो कि विकास और रोजगार सृजक का इंजन है।

अमीरों और कॉर्पोरेट द्वारा कर आय बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। घाटे को पूरा करने के लिए उधारी पहले से ही दिखाई दे रही है। भारत का कर्ज का बोझ पहले से ही भारी है और यह आगे बढ़ता है तो कर्ज चुकाने का बोझ भी बढेगा।

बजट आम आदमी के लिए फेल है, इसे संसद में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। यहां तक कि बजट पूर्व परामर्शों को भी उपहास में बदल दिया गया था और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इसका बहिष्कार कर दिया था।

अंत में, यह मई दिवस–संदेश में ऊपर बताई गई परिस्थितियाँ अधिक प्रासंगिक हैं और श्रमिक वर्ग द्वारा इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

मजदूरों के हितों की रक्षा और हमारे शहीदों की उपलब्धि को बचाने के लिए एकजुट संघर्ष ही हथियार है।

मजदूर एकता जिंदाबाद